

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. विशेष अपील रिट याचिका संख्या 253/2024

मैसर्स ए.के. जिलशान कॉन्ट, अपने प्रोप्राइटर श्री अकरम खान पुत्र श्री रज्जाक के माध्यम से, पंजीकृत कार्यालय ग्राम नीमली, तिजारा, अलवर में स्थित, ट्रक संख्या आरजे-40 जीए-4031 के मालिक।

-----अपीलकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- संयुक्त सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भरतपुर।
- जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर।
- जिला परिवहन अधिकारी, भिवाड़ी, जिला अलवर।

-----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री राजकुमार गोयल
प्रतिवादी के लिए	:	श्री एस.एस. नारुका, अपर महाधिवक्ता, श्री विक्रम शर्मा और श्री

दिव्यांशु गुप्ता द्वारा

सहायता प्राप्त

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

25/07/2024

1. सुना गया।

2. यह अपील माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.02.2024 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी गई है, हालांकि उसे अपील का सांविधिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त और सटीक निवेदन यह है कि यद्यपि एक वैकल्पिक उपचार मौजूद है, असाधारण परिस्थितियों में, मुख्य रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने की मांग की। उनका निवेदन है कि लाइसेंस के निलंबन से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं

दिए जाने के संबंध में याचिका में किए गए जोरदार कथन के विपरीत, प्रतिवादियों ने नोटिस की वास्तविक तामील साबित करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर रखे बिना एक अस्पष्ट और टालमटोल वाला जवाब दिया।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि जिस आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या सांविधिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1988') की धारा 53 पंजीकरण के निलंबन का प्रावधान करती है।

प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार है:-

"53. पंजीकरण का निलंबन.-(1) यदि किसी पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य निर्धारित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कोई मोटर वाहन-

(क) ऐसी स्थिति में है कि सार्वजनिक स्थान पर उसका उपयोग जनता के लिए खतरा पैदा करेगा, या वह इस अधिनियम या उसके तहत बनाए

गए नियमों की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, या

(ख) वैध परमिट के बिना किराए या इनाम के लिए उपयोग किया गया है, या किया जा रहा है, प्राधिकारी, मालिक को कोई भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के बाद, जो वह करना चाहे (मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा, पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज उसके पते पर पावती सहित नोटिस भेजकर), लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित कर सकता है--

(i) खंड (क) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, जब तक दोष उसकी संतुष्टि के अनुसार सुधार किया गया; और

(ii) खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, चार महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं।

(2) पंजीकरण प्राधिकारी के अलावा कोई अन्य प्राधिकारी, उप-धारा (1) के तहत निलंबन आदेश देते समय, ऐसे निलंबन के तथ्य और उसके कारणों को उस पंजीकरण प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में निलंबन के समय वाहन है।

(3) जहां उप-धारा (1) के तहत एक मोटर वाहन का पंजीकरण एक महीने से कम की निरंतर अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है, वह पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन था जब पंजीकरण निलंबित किया गया था, यदि वह मूल पंजीकरण प्राधिकारी नहीं है, तो उस प्राधिकारी को निलंबन की सूचना देगा।

(4) एक मोटर वाहन का मालिक, पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य निर्धारित प्राधिकारी की मांग पर, जिसने इस धारा के तहत वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है, पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंपना।

(5) उप-धारा (4) के तहत सौंपे गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को मालिक को तब लौटाया जाएगा जब पंजीकरण निलंबित करने का आदेश रद्द कर दिया गया हो और उससे पहले नहीं।"

6. कानून का प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि पंजीकरण प्राधिकारी या कोई अन्य निर्धारित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में कोई मोटर वाहन ऐसी स्थिति में है, जैसा कि उप-धारा (1) के खंड ए और बी में वर्णित है, तो प्राधिकारी को मालिक को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना आवश्यक है, जो वह करना चाहे (मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा, पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज उसके पते पर पावती सहित नोटिस भेजकर)

और, उसके बाद, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन का आदेश पारित करना होगा।

7. पंजीकरण को निलंबित करने की शक्ति सांविधिक प्रकृति की है और इसलिए, इसे कानून के तहत प्रदान किए गए तरीके से और किसी अन्य तरीके से प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जहां सांविधिक प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करता है, वहां उसका कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है और इससे कोई बच नहीं सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जहां नोटिस तामील किया गया था और अपीलकर्ता ने उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के बावजूद कोई प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया।

8. हमने पक्षों द्वारा किए गए अभिवचन का अवलोकन किया है। अपीलकर्ता ने रिट याचिका में हलफनामे पर एक स्पष्ट कथन किया है कि उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने केवल टालमटोल वाला जवाब दिया है कि एक नोटिस जारी किया गया था। जहां यह आरोप है कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, यह कहना पर्याप्त नहीं है कि नोटिस जारी किया गया था। प्राधिकारी को शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत निर्धारित तरीके से नोटिस की तामील का प्रमाण रिकॉर्ड पर रखकर न्यायालय को संतुष्ट करना आवश्यक है। प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसे रिट

याचिका में चुनौती दी गई थी, हालांकि उसमें यह कथन है कि नोटिस जारी किया गया था, वह नोटिस की तामील के संबंध में किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं करता है।

9. पिछली सुनवाई की तारीख पर, हमने प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता से न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता को नोटिस की तामील का प्रमाण युक्त प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अपेक्षा की थी। हालांकि, राज्य के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं जिससे यह संतुष्टि हो सके कि जो नोटिस जारी किया गया बताया गया है, वह कानून के तहत निर्धारित तरीके से अपीलकर्ता को तामील किया गया था। अधिनियम, 1988 की धारा 53 में निहित प्रावधान में कहा गया है कि मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा, पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज पते पर पावती सहित नोटिस भेजकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। इन सभी आवश्यक तथ्यों को न्यायालय को यह संतुष्ट करने के लिए साबित करना आवश्यक है कि सांविधिक अधिदेश का पालन किया गया है।

10. यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के गैर-अनुपालन के संबंध में केवल इस आधार पर शिकायत उठाई है कि प्रतिवादियों की कार्रवाई के परिणामस्वरूप सिविल परिणाम होते हैं। यह ऐसा मामला है जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को

सांविधिक योजना में ही शामिल किया गया है, इसलिए यह केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि कानून के तहत प्रदत्त अधिकार से अधिक की कार्रवाई भी है।

11. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, प्रतिवादियों की कार्रवाई प्रारंभ से शून्य है और पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित चुनौतीपूर्ण आदेश केवल उसी आधार पर रद्द किए जाने योग्य है। हम पाते हैं कि इस मामले के इस पहलू को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सराहना की गई नहीं थी। यह सच है कि अपीलकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार है, हालांकि, निर्णयों की बहुतायत में यह कानून सुस्थापित है कि इस नियम के अपवाद हैं जहां रिट न्यायालय वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इच्छुक हो सकता है। असाधारण आधारों में से एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह सुनवाई के अवसर का पूर्ण अभाव का मामला है।

12. इसलिए, इन परिस्थितियों में माननीय एकल न्यायाधीश अपीलकर्ता को उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का उपयोग करने के लिए वापस भेजने में उचित नहीं थे, बल्कि मामले को उसके गुणों के आधार पर तय किया जाना चाहिए था, हालांकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के मुद्दे तक सीमित, मामले को वापस भेजने के बजाय। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान मामला

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन का है जो आदेश को प्रारंभ से शून्य बनाता है। इसलिए, मामले को माननीय एकल न्यायाधीश को वापस भेजने के बजाय, हम मामले को यहीं तय करने के इच्छुक हैं।

13. तदनुसार, प्रतिवादियों द्वारा पंजीकरण को निलंबित करने का निर्णय अवैध घोषित किया जाता है और पंजीकरण का निलंबन तत्काल रद्द कर दिया गया। हालांकि, प्रतिवादियों को कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता है।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाता है। रिट याचिका उपरोक्त निर्देशानुसार स्वीकार की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाया गया।

(आशुतोष कुमार), न्यायमूर्ति (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायाधीश

एन. गांधी/राहुल/514

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022

